5657 Orel Answers

Shri Bibudhendra Misra: Who said so. The question was. 'What was the quality ten years ago'?

Mr. Speaker: No, it was whether deterioration has taken place in so far as the quality ten years ago is concerned and the one that we have got now.

Shri Bibudhendra Misra: About the rise in price since 1957, it is for different reasofts. I have got a lengthy statement. If I am permitted, I will put it on the Table of the House.

Mr. Speaker: Next question Shri Madhu Limaye.

Payment of Wages Act

+547. Shri Madhu Limaye: Shri Kishen Pattnayak: Shri Utiya:

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of cases in the various States under the Payment of Wages Act involving the Railways;

(b) the losses suffered by the Railways as a result of this litigation; and

(c) whether the Railways propose to devise a machinery for examining the workers' claims in the light of the court judgments in these cases?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) The number of cases involving the Railways in the various States under the Payment of Wages Act during the years 1964 and 1965 was 1837 and 973 respectively.

(b) The amount of expenditure incurred by the Railways during the years 1964 and 1965 was Rs. 72,697.58.

(c) Suitable machinery exists on Railways to deal with claims of railway staff in the light of Court judgments in such cases. भी मधु लिमये : मंती महोदय ने बतलामा कि 3,000 ह० का पाटा हुमा। क्या वह उस की तफसील देंगे, क्योंकि मेरा खयाल है कि रेलवे वकीलों वगैरह के ऊपर जितना खर्च करती है वह इतना ज्यादा होता है जिस का टिकाना नहीं है, ग्रौर कभी कभी ग्रदालतों से जुर्माना भी होता है। एक ग्रर्स से मैं यह शिकायतें सुन रहा हूं। इस लिए क्या मंत्री महोदय इस की तफसील देंगे।

डा॰ राम सुभग सिंह: शिकायतें आप सुनते होंगे, लेकिन जो कुछ मैं ने कहां वह आप ने नहीं सुना क्योंकि मैं ने 72,697.58 रु॰ की बात कही और आप केवल 2,000 रु॰ की बात कहते हैं। हो सकता है कि आप शिकायतें भी इसी तरह सुनते हों।

श्वी मधु लिमये : मंत्री सहोदय 72 हजार रु० की तफसील नहीं दे रहे हैं कि वह कैंसे खर्च हए ।

डा० राम सुभग सिंहः चूंकि ग्राप ने पहले कहा कि ग्राप क्रिकायतें सुनते हैं, इस लिये मैं ने कहा कि जिस तरह से ग्राप ने मेरी 72 हजार की ग्रावाज केवल 2 हजार सुना उसी प्रपोर्शन में शायद ग्राप शिकायतें भी सुनते होंगे । जहां तक तकसील का सवाल है ग्राप जितनी चाहें मैं टेबल पर रख दुंगा ।

<mark>भ्राध्यक्ष मह</mark>ोदयः श्राप उस को टेबल पर रख दीजिये ।

श्री मधु लिसये माननीय मत्नी कहते हैं कि मजदूरों के दावों की जांच पड़ताल के लिये उन के पास काफी इन्तजाम है । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या उन्होंने जो रेलवे मजदूरों की ट्रेड यूनियन्स हैं उन को बातचीत करने के लिये बुलाया था। मजदूरों के दावों की जांच करने के लिये क्या इन्तजाम है ग्रीर उस में क्या मुधार हो सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है।

डा० राम सुभग सिंहः जैसा कि सारे माननीय सदस्य जानते हैं, परमानेन्ट नेगोशि-

5659 Oral Anewers SRAVANA 28. 1888 (SAKA) Oral Answers 5660

एटिंग मशीनरी रेलवे में है। जो कोई शिकायत होती है उस की हर स्टेज पर जांच की जाती है। बातें होती हैं और वह ग्रज़ेन्डा पर ग्राती हैं। मजदूरों के फेडरेशन्स और यूनियन्स की रांय से ही वे कहती हैं कि किन-किन चीजों को हमें लेना चाहिये। सारी बातें डिस्कस की जाती हैं।

श्वी मखु लिमये: ग्रगर ग्राज तक ऐसा नहीं हुग्रा है तो क्या अविष्य के लिये ग्राप इस विषय की जांच करेंगे ताकि यह खर्च घटे।

डा० राम मुभग सिंहः ग्रब इस को बदलने की बात मैं कैसे करूं। जितनी शिकायतें हैं खुद फेडरेशन ग्रीर जोनल यनियन्स

श्री मबु जिमयेः मैं शिकायतें ग्राप के सामने रक्खू तो उस पर भी ग्राप को विचार करना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह ः जब तक वह फेडरेशन से नहीं ग्रायेंगी, मैं नहीं मान्गा ।

श्री ग्र॰ प्र॰ शर्मा : जो पेमेन्ट ग्राफ वेजेज ऐक्ट के केसेज़ होते हैं ग्रीर रेलवे मजदूरों को पेमेन्ट ग्राफ वेजेज ऐक्ट के नीचे मुग्रावजे का पेमेन्ट करना होता है, उस के लिये क्या रेलवे मंत्रालय ने जो लोग जिम्मेदार हैं उन को जिम्मेदार ठहराया है, जिस की वजह से रेलवे को इतना पेमेन्ट करना होता है। ग्रगर ऐसा किया है तो जिस ने ऐसी कार्रवाई की है उस के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जा रहा है।

डा॰ राम सुभग सिंहः किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात नहीं याती । 18 लाख के करीब रेलवे एम्प्लायी हैं लेबरर्स को मिला कर। जितने कैंसेज हुए हैं 1965 में उन की कुल तादाद 973 है । इस लिये धगर कहीं इंटरप्रेटेशन का झगड़ा हो तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई कैंसे की जाये । Shri A. P. Sharma: Under the Payment of Wages Act, if the Railways are made to pay compensation and also wages to the workers, then somebody must be responsible for not paying the wages in time and, if that is so, then responsibility should be fixed on the officials, whoever they may be, and action should be taken. There are 900 and odd cases. It would be better if the Government fixes up the responsibility so that there will not be a single case under the Payment of Wages Act. Will the Government do that?

Mr. Speaker: How is it possible that there might not be a single case? There may be a difference of opinion on interpretation.

Shri A. P. Sharma: The number of cases will be less.

Mr. Speaker: The number of cases might be less. But how is it possible that there might not be a single case? Lawyers always differ on interpretation.

Dr. Ranen Sen: In the general industrial field, we find that there is a gradual reduction of cases under the Payment of Wages Act which shows that even in the private sector, they have geared up their administration and organisation in such a manner that the cases are fewer and fewer. But in the Railways, which is the biggest Government organisation, which is considered to be a very efficient organisation, how is it that the cases under the Payment of Wages Act continue without any reduction in their number?

Dr. Ram Subhag Singh: Here also, in 1964, the total number of cases was 1887 and in 1965, it came down to 973. So, here also, there is a decrease in the number of cases.

Shri S. M. Banerjee: I would like to know whether it has been brought to the notice of the hon. Minister that when casual labourers are paid, whether on South-Eastern Railway or on any other Railway, they are sometimes paid less, Rs. 5 less or Rs. 10 less, whatever it may be, because there is no check on that and, if so, whether adequate steps have been taken to see that they are paid correctly and that they are not paid less.

5661 Oral Answers

Dr. Ram Subhag Singh: If any case of incorrect payment is reported to us, we will take suitable action.

Shri U. M. Trivedi: I would like to know from the Minister whether, from the time that this new amendment has been made to the Payment of Wages Act through the iniquitous legislation which was brought forward in the last session by the Labour Minister, Shri D. Sanjivayya, the Railways have benefited in terms of money by deducting money from the meagre wages of booking clerks, ticket collectors and cash clerks for having accepted notes forged by somebody or for having been victims of pilfering or stealing from their own cash counters.

Dr. Ram Subhag Singh: That might be his experience. We have no experience like that.

Shri U. M. Trivedi: You say that you have not got that experience. Are you, in that case, prepared to withdraw the amendment which you brought into this Act that the money that can be stolen by anybody....

Mr. peaker: About that he can write now.

Shri U. M. Trivedi: This is a very important thing. I will write to him. But the whole difficulty is that the Railway Minister always drags on matters for years. Nothing comes to an end.

Mr. Speaker: He might send a copy to me. Next Question.

Import of Staple Fibre

+ *548. Shri Madhu Limaye: Shri Kishen Patmayak: Shri Bagri: Dr. Ram Manohat Lohia:

Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4735 on the 29th April, 1966 and state:

(a) whether Government have completed the investigation regarding the issue of licences for the import of staple fibre;

(b) if so, the result thereof;

(c) the names of the parties who have been found to be guilty of violations of Government regulation and the punishment imposed on these parties; and

(d) the steps taken to prevent recurrence of such violations?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) to (c). The matter is stillunder investigation.

(d) The import of non-viscose staple fibre under the Cotton Textiles Export Scheme is not allowed with effect from the 1st January, 1965.

की मधु लिपये ः क्या मंत्री महोदय के पास इस बात की कोई जानकारी है कि यह जो स्टेपल फाइवर मंगाया गया था उसका काले बाजार में क्या दाम है ; किस प्रीमीयम से वह बेचा जाता है ?

श्री मनुभाई ज्ञाहः पूरी जानकारी है । ऊंवे दाम से बेचा जाता है ।

श्वी **सखुलिमये** ः बताइये तो सही जो जानकारी द्याप के पास है । क्या प्रीमियम है ?

श्री मनुभाई शाह : दाम रोज बदलता रहता है । एक ही दाम तो नहीं रहता है

श्वीमधुलिमये: इस वक्त क्यादाम है?

श्री मनुभाई शाह : ग्रभी नहीं बता सकता हूं ।

श्री मधु लिमये : इसमें जो हेराफेरी हुई है क्या यह मंत्रालय से सम्बन्धित किसी दफ्तर में हुई है, यानी टैक्सटाइल कमिश्रनर के दफ्तर में हुई है या और किसी तरीके से यह किया गया है ?